पारादीप बंदरगाह भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में अग्रणी बन गया है

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) की उल्लेखनीय यात्रा वित्त वर्ष 2023-24 में अविश्वसनीय 145.38 एमएमटी कार्गो थ्रूपुट हासिल करने की हालिया रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धि के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और इस तरह से दीनदयाल पोर्ट, कांडला सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाले प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा है। देश की।

पारादीप बंदरगाह के बारे में अधिक जानकारी

- पारादीप भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह ओडिशा राज्य का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है जो कोलकाता से 210 समुद्री मील दक्षिण में और विशाखापत्तनम से 260 समुद्री मील उत्तर में बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी तट पर स्थित है।
- पारादीप पोर्ट अपनी बर्थ उत्पादकता को पिछले वित्तीय वर्ष के 31050 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33014 मीट्रिक टन करने में सक्षम रहा है, इस प्रकार 6.33% की वृद्धि दर्ज की गई है। पारादीप बंदरगाह द्वारा प्राप्त बर्थ उत्पादकता देश के सभी बंदरगाहों में सबसे अधिक है।
- आज की तारीख में 289 मिलियन मीट्रिक टन रेटेड क्षमता वाला पारादीप पोर्ट, वेस्टर्न डॉक परियोजना के चालू होने के साथ अगले 3 वर्षों में 300 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है।
- पारादीप बंदरगाह रेल और सड़क यातायात की सतही क्रॉसिंग से बचने के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से अपने परिसर के भीतर दो सड़क फ्लाईओवर चालू करके कनेक्टिविटी में सुधार करने की योजना बना रहा है। इससे बंदरगाह सड़क यातायात को निर्बाध रूप से संभालने में सक्षम हो जाएगा।
- अपने बंदरगाह नेतृत्व औद्योगीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में, बंदरगाह ने विभिन्न उद्योगों को 769 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिससे 8700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आएगा और इस प्रकार बंदरगाह पर 50 मिलियन मीट्रिक टन यातायात आकर्षित होगा।
- बंदरगाह का लक्ष्य हरित अमोनिया/हरित हाइड्रोजन को संभालने के लिए एक विशेष बर्थ विकसित करने का भी है, जिससे यह देश का हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन जाएगा।
- बंदरगाह आईआईटी, चेन्नई के सहयोग से नवीनतम पोत यातायात प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एक अत्याधुनिक सिग्नल स्टेशन विकसित कर रहा है। इससे सुरक्षा में सुधार के अलावा, जहाज प्रबंधन और समुद्री संचालन में काफी सुधार होगा।

REC ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में SKOCH ESG पुरस्कार 2024 जीता

खबरों में क्यों?

- विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी एनबीएफसी,

आरईसी लिमिटेड को 'नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण' श्रेणी में SKOCH ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार टिकाऊ वित्तपोषण, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को तेज करने के प्रति आरईसी के समर्पण को रेखांकित करता है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- SKOCH ESG पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता देते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं।
- SKOCH ESG पुरस्कार और मूल्यांकन भारत 2047 के लिए संगठनों की प्रतिबद्धता के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
- यह एक स्थायी और बढ़ते व्यावसायिक भविष्य को आकार देने में स्थायी निवेश और प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है।
- आरईसी भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो देश के स्थायी भविष्य में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। विभिन्न पहलों और उपलब्धियों के माध्यम से, आरईसी ने कई टिकाऊ परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता जताई है और हरित परियोजनाओं के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के बारे में

- आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है।
- आरईसी पूरे पावर-इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तपोषित करता है जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करता है।
- आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय के लिए एक नोडल एजेंसी रही है। विद्युत निधि (एनईएफ) योजना जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम-मील वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, 100% गाँव का विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया।
- आरईसी को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है।

व्यायाम 'गगन शक्ति'

खबरों में क्यों?

- भारतीय वायु सेना (IAF) जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा अभ्यास 'गगन शक्ति' आयोजित कर रही है। यह अभ्यास जो शुरू हुआ ओ 10 अप्रैल.

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- अभ्यास में वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं.
- भारतीय सेना मेगा अभ्यास के लिए रसद सहायता प्रदान कर रही है, जिससे आईएएफ के ऑपरेशनल रेल मोबिलाइजेशन प्लान (ओआरएमपी) पहलुओं को मान्य करने के लिए लगभग 10,000 आईएएफ कर्मियों और गोला-बारूद की व्यापक अखिल भारतीय आवाजाही की सुविधा मिल रही है।
- यह अभ्यास जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सहित देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है।
- अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30, जगुआर, ग्लोबमास्टर, चिनूक, अपाचे और प्रचंड समेत कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे।
- यह आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान भारतीय वायुसेना ने दो चरण के हवाई युद्धाभ्यास के दौरान 11,000 से अधिक उड़ानें पूरी की थीं।
- भारतीय सेना के मूवमेंट कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (एमसीओ) के माध्यम से संपर्क और आंदोलन

समर्थन सुनिश्चित किया जा रहा है। मार्ग में एमसीओ को सेना मुख्यालय में स्थापित "एक नियंत्रण कक्ष" के साथ समन्वय में आंदोलन की निगरानी करने का काम सौंपा गया है, जैसा कि ऑपरेशन के दौरान किया जाना है।

भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया

खबरों में क्यों?

- देश ने पहली बार वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2023-24 में 1 बिलियन टन कोयला और लिग्नाइट उत्पादन का मील का पत्थर पार कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 937 मिलियन टन (एमटी) था।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत का कोयला उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) में 997.4 मिलियन टन की नई ऊंचाई को छू गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.67% की वृद्धि है, लेकिन 1 बिलियन टन के लक्ष्य से कम है।
- हालाँकि, कोयले और लिग्नाइट का संचयी उत्पादन रिकॉर्ड 1.04 बिलियन टन के साथ मील के पत्थर को पार कर गया।
- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वित्त वर्ष 24 में 773.6 मिलियन टन जीवाश्म ईंधन का उत्पादन किया, जो साल-दर-साल 10% की वृद्धि है।
- चालू वित्तीय वर्ष के लिए, कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 के अंत तक बिजली क्षेत्र के लिए कोयला आयात को खत्म करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, 838 मिलियन टन का महत्वाकांक्षी उत्पादन और आपूर्ति लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स 206.1 मिलियन टन के उत्पादन के साथ 200 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करने वाला पहला भारतीय कोयला उत्पादक बन गया।
- दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी सीआईएल ने भी कुल आपूर्ति में साल-दर-साल 8.5% की वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 24 में 753.5 मिलियन टन तक पहुंच गई।
- हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष में बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 5.4% बढ़कर 618.5 मिलियन टन हो गई, जो वित्त वर्ष 23 में 586.6 मिलियन टन थी।
- कंपनी ने वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 610 मिलियन टन की तुलना में बिजली संयंत्रों को 8.5 मिलियन टन अधिक कोयले की आपूर्ति करके अपने लक्ष्य को पार कर लिया।

भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चतम स्तर को पार कर गया

खबरों में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि देश का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि है।
- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में निर्यात 15,920 करोड़ रुपये का था। हालिया आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है।
  निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात हासिल करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। निजी क्षेत्र और डीपीएसयू ने क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का योगदान दिया है।
- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा निर्यातकों को जारी किए गए निर्यात प्राधिकरणों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,414 निर्यात प्राधिकरणों से, वित्त वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 1,507 हो गई।
- दो दशकों यानी 2004-05 से 2013-14 और 2014-15 से 2023-24 तक के तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि रक्षा निर्यात में 21 गुना की वृद्धि हुई है।

- 2004-05 से 2013-14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपये था, जो 2014-15 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपये हो गया है।
- रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान के अलावा, सरकार द्वारा लाए गए नीतिगत सुधारों और 'व्यवसाय करने में आसानी' पहल के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई है।
- हालाँकि, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 2014-18 की अवधि की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि के साथ भारत 2019-23 की अवधि के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा।

प्रयास IAS ACADEMY
An Institute for UPSC & BPSC
prayasiasacademy
prayasiasacademy
prayasiasacademy.com

ATTENTION
UPSC / BPSC Aspirants
Boost your AIR with

GS TARGET COURSE
FOR BPSC & UPSC
हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM
MODE: Offline & Online
ADMISSION OPEN upto 50% OFF*